1	2	3	4	5
रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि. बम्बई – 400021	अनिवासी भारतीय	सोया डि- ऑयल्ड केक	राजकोट गुजरात	300.00 (20%)
एल एम पी एग्रो एक्सपोर्ट लि. वदोदरा – 390005	अनिवासी भारतीय	सूखा प्याज और अन्य सब्जियां जैसे कि लहसून,अदरख इत्यादि	वदोदरा गुजरात	187.50 (27%)
अनूप कोठारी नई दिल्ली – 110048	डालसेम वेसियप हालैंड, नीदरलैंड	सफेद बटन मशरूम	वदोदरा गुजरात	160.00
कामसन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., गुजरात	मल्टीफ्लोर हालैंड, एन. वी., हालैंड, नीदरलैंड	ताजे फूल जैसे कि गुलाब, क्राईसेंथेमम, कारनेशन जरवेरा (ग्रीन हाउस कल्टीवेल शन के अधीन उपजाए गए)	वदोदरा गुजरात	90.65 (49%)
राधेश्याम एग्रो फूड्स लि. अहमदाबाद-380001	बेल्लभई बार्टर ट्रेड प्रा. लि. सिंगापुर	आलू पाउडर	गुजरात	64.00 (6.32%)

राज्यों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए प्रदान की गई राशि

546. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षो के दौरान गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए रज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की है,

(ख) क्या इन सभी राज्यों ने इस राशि का समुचित उपयोग किया है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार इस योजना के लिए निर्धारित सिद्धांतों में संशोधन करने का विचार रखती हैं,

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीब लोगों को प्रभावी ढंग से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उठाए जाने का विचार हैं?

विधि न्याय और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति, विधिक सहायता शिविर लगाने, लोक आदोंलनों आयोजित करने, विधि सहायता क्लिनिक स्थापित करने, विधिक ज्ञान के संवर्द्धन, पराविधिकों के प्रशिक्षण जैसे विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डो, विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों और सामाजिक कार्य समूहों को सहायता अनुदान मंजूर करती है। वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यवार दिया गया हिसाब सदन के पटल पर रखे गए विवरण में अंतर्विष्ट हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उपयोग न किए जाने के कारण विधि और व्यवस्था, बाढ़ सूखा और व्यावसायिकों के रूख, आदि के कारण भिन्न हो सकतें हैं।

(घ) और (ड़) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(च) निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संघ सरकार द्वारा की गई वित्तीय सहायता से राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डो द्वारा लोक अदालतें, विधिक सहायता शिविर, विधिक ज्ञान शिविर पराविधिकों के प्रशिक्षण, आदि जैसे विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 **और** 1994-95 **के दौरान राज्यवार मंजूर किए गए सहायता अनुदान की रकम और उसकी अनुदान प्राप्त संस्थानों द्वारा दिए गए हिसाब**

राज्य का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
	अनुदान की रकम रु0	**दिया गया हिसाब रु0**	**अनुदान की रकम रु0**	**दिया गया हिसाब रु0**	**अनुदान को रकम रु0**	**दिया गया हिसाब रु0**
आंन्ध्र प्रदेश	1,16,000	50,000	2,70,000	20,000	55,000	*हिसाब
असम	25,000	25,000	1,10,000	5,000	1,10,000	30 जून,
बिहार	60,000	50,000	70,000	10,000	5,000	1995 तक
गुजरात	1,75,136	1,15,136	1,25,000	1,00,000	1,00,000	-
हरियाणा	1,65,000	1,65,000	5,000	-	1,75,000	20,000
हिमाचल प्रदेश	1,00,000	1,00,000	-	-	50,000	-
जम्मू कश्मीर	-	-	-	-	10,000	-
कर्नाटक	2,70,000	2,60,000	2,50,000	-	2,00,000	-
केरल	1,10,000	1,10,000	10,000	10,000	1,10,000	-
मध्य प्रदेश	2,20,000	2,10,000	1,00,000	-	1,15,000	5,000
महाराष्ट्र	1,45,000	1,45,000	5,000	-	-	-
मणिपुर	10,000	10,000	10,000	-	-	-
उड़ीसा	3,27,000	2,63,000	2,60,000	20,000	1,00,000	20,000
पंजाब	25,000	25,000	75,000	75,000	50,000	*
राजस्थान	-	-	15,000	15,000	15,000	*
उत्तर प्रदेश	25,000	25,000	1,70,000	1,30,000	2,55,000	*
पश्चिमी बंगाल	95,000	65,000	60,000	55,000	30,000	*
दिल्ली	9,74,500	9,74,500	9,55,000	1,30,000	8,95,000	*

Meteorological Forecasts

547. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the meteorological forecasts put out every day this season have turned out to be highly erratic and unreliable;

(b) whether such forecasts have totally failed to predict the abnormal delay in monsoon in many northern parts of the country thereby misleading the farmers; and

(c) if so, whether Government would consider stopping issue of generalised long-term forecasts and develop a regional forecasting mechanism for predominantly rain-fed areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND SPACE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (•) No Sir. Short range forecasts issued by India Meteorological Department on a day-today basis have been found to be reasonably accurate.

(b) No long range forecast was made about the onset of monsoon over North India by IMD.

(c) No Sir, long range forecast of southwest monsoon range is useful for planning purposes and is required by differnet agencies. It is supplemented by short range forecast for regional/sub-rcgional levels.